



Daily करेंट अफेयर्स

➤ 01 सितम्बर 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) 2023-24 जारी किया: तमिलनाडु कारखानों और रोजगार में शीर्ष पर, महाराष्ट्र GVA में सबसे आगे।



सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) के परिणाम जारी किए हैं, जिसे ASI 2023-24 कहा गया है। यह सर्वेक्षण भारत के औद्योगिक प्रदर्शन पर प्रकाश डालता है, जिसमें तमिलनाडु कारखानों और रोजगार के मामले में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है।

- ASI 2023-24 के लिए फील्डवर्क अक्टूबर 2024 और जून 2025 के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर में विनिर्माण इकाइयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया था।

- यह सर्वेक्षण रोजगार, पूंजी निवेश, सकल मूल्य संवर्धन और औद्योगिक उत्पादन पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे यह औद्योगिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन जाता है।

- तमिलनाडु को कारखानों की संख्या और विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल व्यक्तियों, दोनों के संदर्भ में अग्रणी राज्य के रूप में पहचाना गया। भारत भर में 2.60 लाख कारखानों में से, तमिलनाडु

का हिस्सा 15.43% है, जिसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है।

Key Points:-

(i) उद्योगों में स्थायी पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 23 में ₹41,21,79,458 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में ₹46,24,09,035 करोड़ हो गई। निवेशित पूंजी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के ₹61,39,21,255 करोड़ की तुलना में ₹68,01,32,999 करोड़ तक पहुँच गई, जो मजबूत औद्योगिक विस्तार को दर्शाता है।

(ii) रोजगार के स्तर में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की गई, कुल रोजगार वित्त वर्ष 23 में 1,84,94,962 व्यक्तियों से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 1,95,89,131 व्यक्तियों तक पहुँच गया। एसआई ने आगे बताया कि 2014-15 और 2023-24 के बीच इस क्षेत्र में 57 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ जुड़ी हैं, जो विनिर्माण को रोजगार के एक प्रमुख कारक के रूप में रेखांकित करता है।

(iii) सकल मूल्य वर्धन (GVA) के संदर्भ में, इस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 11.89% की वृद्धि दर्ज की। GVA योगदान में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा, उसके बाद गुजरात और तमिलनाडु का स्थान रहा। विकास को गति देने वाले प्रमुख उद्योग मूल धातु, मोटर वाहन, रासायनिक एवं औषधि उत्पाद, और खाद्य उत्पाद थे, जिनमें गुजरात उत्पादन मूल्य और स्थायी पूंजी के मामले में शीर्ष पर रहा, जबकि कार्यबल और कारखानों की संख्या के मामले में तमिलनाडु का दबदबा रहा।

2. PMJDY के 11 वर्ष पूरे: 2.68 लाख करोड़ रुपये जमा के साथ 56.16 करोड़ खाते खोले गए।



28 अगस्त, 2025 को, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) अपनी 11वीं वर्षगांठ मनाएगी, जो वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई PMJDY का उद्देश्य, विशेष रूप से वंचित आबादी के लिए, बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना था। 13 अगस्त, 2025 तक, इस योजना ने 56.16 करोड़ खाते सफलतापूर्वक खोले हैं, जिनमें कुल जमा राशि ₹2.68 लाख करोड़ है, जो वित्तीय परिदृश्य पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है।

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के कार्यान्वयन और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने वक्तव्य में, वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वित्तीय समावेशन आर्थिक वृद्धि और विकास का एक प्रमुख चालक है।

- उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बैंक खातों तक सार्वभौमिक पहुंच से गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने में मदद मिलती है, जिससे समावेशी विकास में योगदान मिलता है।

- PMJDY की एक उल्लेखनीय उपलब्धि महिलाओं और ग्रामीण आबादी पर इसका ध्यान केंद्रित करना है। लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं, और 67%

खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। यह जनसांख्यिकीय पहुँच सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय समावेशन का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुँचे।

Key Points:-

(i) इस योजना के तहत 38 करोड़ से ज़्यादा RuPay डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक पर ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। ये कार्ड डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और खाताधारकों के लिए वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

(ii) PMJDY ने भारत की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लाभार्थियों के खातों में कल्याणकारी लाभों को सीधे जमा करने का एक मंच प्रदान करके, इस योजना ने लीकेज को कम किया है, भ्रष्टाचार को न्यूनतम किया है और यह सुनिश्चित किया है कि सब्सिडी इच्छित लाभार्थियों तक शीघ्र पहुँचे।

(iii) PMJDY अपने 12वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और यह भारत की JAM (जन धन, आधार, मोबाइल) त्रिमूर्ति को मज़बूत बना रही है, शासन दक्षता बढ़ा रही है और नागरिकों के लिए एक मज़बूत वित्तीय सुरक्षा जाल तैयार कर रही है। इस योजना की सफलता समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि देश 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए कोई भी नागरिक पीछे न छूटे।

3. स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने AI इनोवेटर्स को स्पॉटलाइट करने के लिए IndiaAI मिशन के साथ साझेदारी में 'IndiaAI इन एक्शन' पॉडकास्ट लॉन्च किया।

STARTUP POLICY FORUM LAUNCHES

'IndiaAI in Action' PODCAST

IN PARTNERSHIP WITH



**IndiaAI
INNOVATORS**



स्टार्टअप पॉलिसी फोरम (SPF) ने IndiaAI मिशन के सहयोग से IndiaAI इन एक्शन नामक एक नई पॉडकास्ट श्रृंखला का अनावरण किया है, जो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को हल करने और सामाजिक और व्यावसायिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का लाभ उठाने वाले भारतीय स्टार्टअप की कहानियों को जीवंत करती है।

- पॉडकास्ट का शुभारंभ फरवरी 2026 में नई दिल्ली में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट से पहले हुआ है, जहां वैश्विक नेता, राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष प्रौद्योगिकी अधिकारी जिम्मेदार AI परिनियोजन के भविष्य को आकार देने के लिए एकत्र होंगे।

- सीज़न वन में प्रमुख संस्थापक और सह-संस्थापक शामिल हैं: रेज़रपे के हर्षिल माथुर, सर्वम AI के विवेक राघवन, इनवीडियो के संकेत शाह और अंशुल खंडेलवाल, और इक्सिगो के रजनीश कुमार के साथ आलोक बाजपेयी।

Key Points:-

(i) यह श्रृंखला इन उद्यमियों की गतिशील यात्राओं को दर्शाती है, और इस बात पर प्रकाश डालती है कि वित्तीय प्रौद्योगिकी, यात्रा, स्वास्थ्य सेवा, सामग्री निर्माण और उद्यम समाधानों में एआई का उपयोग कैसे किया जा रहा है। बेबाक कहानी कहने के माध्यम से, संस्थापक यह प्रदर्शित करते हैं कि वे

भारत के विकसित होते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को कैसे बढ़ा रहे हैं और नवाचार को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं।

(ii) यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत IndiaAI मिशन द्वारा समर्थित है, और यह दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले क्लाउड प्लेटफॉर्म वल्ट्र द्वारा संचालित है, जो 32 वैश्विक डेटा केंद्रों में 220,000 से अधिक ग्राहकों का समर्थन करता है।

(iii) स्टार्टअप पॉलिसी फोरम की अध्यक्ष और CEO श्वेता राजपाल कोहली ने कहा कि "IndiaAI इन एक्शन का उद्देश्य दूरदर्शी संस्थापकों और अत्याधुनिक AI उपयोग मामलों पर प्रकाश डालकर एआई नवाचार को प्रेरित, शिक्षित और सक्रिय करना है," जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के भीतर AI को तेजी से अपनाने पर जोर देता है।

4. भारत में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार, शिक्षा मंत्रालय ने UDISE+ 2024-25 रिपोर्ट जारी की।



अगस्त 2025 में, शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) के नवीनतम निष्कर्ष जारी किए। इस रिपोर्ट में भारत की स्कूली शिक्षा पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की गई है, जिसमें पहली बार 1 करोड़ शिक्षकों की संख्या पार करने के

ऐतिहासिक मील के पथर सहित प्रमुख उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

- UDISE+ 2024-25 रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में स्कूल शिक्षकों की कुल संख्या 1,01,22,420 से अधिक हो गई है, जो 2018-19 में इस प्रणाली की शुरुआत के बाद पहली बार 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। यह आंकड़ा 2023-24 में 98,07,600 और 2022-23 में 94,83,294 शिक्षकों की तुलना में वृद्धि दर्शाता है, जो शिक्षण कार्यबल में साल-दर-साल लगातार वृद्धि दर्शाता है।

- रिपोर्ट का एक प्रमुख आकर्षण 2014-15 की तुलना में सभी शैक्षिक स्तरों पर छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) में सुधार था। आधारभूत स्तर पर PTR 15 से बढ़कर 10, प्रारंभिक स्तर पर 18 से बढ़कर 13, माध्यमिक स्तर पर 26 से बढ़कर 17 और माध्यमिक स्तर पर 31 से बढ़कर 21 हो गया, जो अधिक केंद्रित शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाता है।

- शिक्षकों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, रिपोर्ट में छात्र नामांकन में गिरावट दर्ज की गई। कक्षा एक से बारहवीं तक नामांकित छात्रों की कुल संख्या में 11 लाख की कमी आई, जो 2023-24 में 24.8 करोड़ से घटकर 2024-25 में 24.69 करोड़ रह गई। यह 2018-19 में UDISE+ डेटा संग्रह शुरू होने के बाद से सबसे कम नामांकन आंकड़ा है, जिससे औपचारिक शिक्षा में दीर्घकालिक भागीदारी को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

Key Points:-

(i) सकारात्मक बात यह है कि रिपोर्ट में तीनों प्रमुख स्कूल स्तरों—प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक—में स्कूल छोड़ने की दर में गिरावट पर प्रकाश डाला गया है। पिछले वर्षों (2022-23 और 2023-24) की तुलना में, 2024-25 में समय से पहले स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम रही, जो छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन योजनाओं और डिजिटल शिक्षण पहलों जैसे

निरंतर सरकारी हस्तक्षेपों के प्रभाव को दर्शाता है।

(ii) आंकड़ों से सकल नामांकन अनुपात (GER) में, विशेष रूप से मध्य और माध्यमिक स्तर पर, उत्साहजनक वृद्धि का पता चला है। मध्य स्तर पर GER 89.5% से बढ़कर 90.3% हो गया, जबकि माध्यमिक स्तर पर GER 2024-25 में 66.5% से बढ़कर 68.5% हो गया। ये आंकड़े छात्रों को बनाए रखने में हुई प्रगति को दर्शाते हैं, खासकर मध्य से उच्च कक्षाओं में संक्रमण के दौरान।

(iii) 2018-19 में अपनी शुरुआत के बाद से, UDISE+ भारत में सबसे व्यापक स्कूली शिक्षा डेटाबेस बन गया है, जिसमें शिक्षक संख्या, नामांकन, बुनियादी ढाँचा और प्रदर्शन के पैमाने शामिल हैं। 2024-25 का संस्करण शिक्षकों की एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के साथ-साथ नामांकन में गिरावट जैसी चुनौतियों की पहचान करने के लिए भी उल्लेखनीय है, जिससे शिक्षा मंत्रालय के तहत भविष्य की शिक्षा नीतियों का मार्गदर्शन होता है।

5. विद्युत मंत्रालय ने 6वां राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और असम को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बताया गया।



अगस्त 2025 में, विद्युत मंत्रालय (MoP) ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की प्रगति का

आकलन करने हेतु राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024 का छठा संस्करण जारी किया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन (AEEE) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया यह सूचकांक, विद्युत मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और BEE के महानिदेशक आकाश त्रिपाठी द्वारा जारी किया गया।

- SEEI 2024 ने ऊर्जा दक्षता के विभिन्न संकेतकों पर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया, जिसमें भवन, उद्योग, परिवहन, कृषि और विभिन्न क्षेत्रों की पहल जैसे मांग वाले क्षेत्र शामिल थे। यह सूचकांक इस बात की तुलना करने के लिए एक मानक उपकरण बन गया है कि राज्य राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा दक्षता उपायों को कैसे लागू करते हैं।

- सूचकांक के अनुसार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा अपने-अपने समूहों में अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल रहे। समूह 1 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, जबकि समूह 2 में आंध्र प्रदेश, समूह 3 में असम और समूह 4 में त्रिपुरा शीर्ष पर रहा। यह वर्गीकरण राज्यों की कुल ऊर्जा खपत पर आधारित था, जिसे मिलियन टन तेल समतुल्य (MTOe) में मापा गया था।

- SEEI 2024 ने प्रदर्शन स्कोर के आधार पर राज्यों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया: अग्रणी (60% से ऊपर), सफल (50-60%), दावेदार (30-50%), और आकांक्षी (30% से नीचे)। यह वर्गीकरण राज्यों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालता है और दक्षता में तेज़ी लाने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

Key Points:-

(i) रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में अग्रणी राज्यों की संख्या सात से घटकर पाँच हो गई है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने इस

शीर्ष प्रदर्शन श्रेणी में अपना स्थान बरकरार रखा है। इस बीच, असम और केरल जैसे राज्यों ने अपने स्कोर में सुधार करते हुए अचीवर्स श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है।

(ii) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों को प्रतियोगी श्रेणी में रखा गया, जो दक्षता कार्यान्वयन में मध्यम प्रगति दर्शाता है।

(iii) SEEI 2024, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुरूप 2030 तक ऊर्जा तीव्रता को कम करने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य स्तर पर निरंतर नीतिगत प्रयासों, वित्तपोषण तंत्र और क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर देता है।

6. बिहार कैबिनेट ने महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को मंजूरी दी।



29 अगस्त 2025 को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी, जो एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता, कौशल विकास और उद्यमशीलता के अवसरों के साथ महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी को मजबूत करना है।

● इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार से एक महिला की पहचान की जाए और उसे स्व-रोज़गार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। शुरुआत में, प्रत्येक चयनित लाभार्थी को ₹10,000 का प्रत्यक्ष अनुदान मिलेगा, जबकि छह महीने की कार्य-निष्पादन समीक्षा के बाद ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

● ग्रामीण विकास विभाग (RDD) गांवों में कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगा, जबकि शहरी विकास एवं आवास विभाग (UDHD) कस्बों और शहरों में गतिविधियों की देखरेख करेगा।

● लाभार्थी निधियों को सितंबर 2025 से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तंत्र के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे संवितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

Key Points:-

(i) मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के अनुसार, यह कार्यक्रम महिला संवाद अभियान के दौरान व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था, जिसमें जमीनी स्तर पर जरूरतों का आकलन करने के लिए 70,000 से अधिक महिला समूहों को शामिल किया गया था।

(ii) यह योजना बिहार की महिला-केंद्रित पहलों, जैसे पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण (2006), शराबबंदी कानून (2016), और छात्राओं के लिए साइकिल एवं छात्रवृत्ति योजनाओं, की निरंतरता को दर्शाती है। यह जीविका स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क का भी लाभ उठाती है, जो वर्तमान में 11 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1.4 करोड़ महिलाओं को जोड़ते हैं, जिससे नई योजना को एक तैयार सामाजिक आधार मिलता है।

(iii) बिहार में रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित करके, इस पहल का उद्देश्य काम के लिए युवाओं और

महिलाओं के पलायन को कम करना है। यह न केवल स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देता है, बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, जो लैंगिक समानता और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

7. HCLटेक, पियर्सन इंडिया और MeitY स्टार्टअप हब ने 'अराइज फॉर यू' उद्यमिता चुनौती शुरू की।



27 अगस्त, 2025 को, HCL टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (HCLTech) ने पियर्सन इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत आने वाले MeitY स्टार्टअप हब (MSH) के साथ साझेदारी में, एक नवाचार-संचालित उद्यमिता चुनौती, 'अराइज (Aspire.Rise.Inspire.Skill.Excel) फॉर यू' शुरू की। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के लिए उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना और भारत सरकार के विकसित भारत मिशन के साथ तालमेल बिठाना है।

● यह कार्यक्रम देश भर के छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका अंतिम कार्यक्रम 12-13 मार्च, 2026 को निर्धारित है। विजेताओं को नकद अनुदान, मेंटरशिप, इनक्यूबेशन सहायता और राष्ट्रीय मीडिया मान्यता प्रदान की जाएगी।

● इस चुनौती ने देश भर के 3,000 से ज्यादा परिसरों से 1,50,000 से ज्यादा छात्रों को आकर्षित किया है, जिससे यह भारत में उद्यमिता की सबसे बड़ी पहलों में से एक बन गई है। प्रतिभागी प्रतियोगिता के कई चरणों में भाग लेंगे, जिसका ग्रैंड फ़ाइनल मार्च 2026 में समाप्त होगा।

● पियर्सन इंडिया उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय (ESB) प्रमाणन प्रदान करेगा और संरचित शिक्षण सामग्री प्रदान करेगा, जबकि मीटी स्टार्टअप हब (MSH) प्रतिभागियों के लिए मेंटरशिप, इनक्यूबेशन और परामर्श के अवसरों की सुविधा के लिए 62 क्षेत्रीय केंद्रों सहित अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाएगा।

Key Points:-

(i) विजेता टीमों ₹10 लाख तक के अनुदान, अपने उद्यमशीलता उपक्रमों के लिए इनक्यूबेशन सहायता और राष्ट्रीय मीडिया कवरेज के अवसरों के लिए पात्र होंगी। इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य युवा उद्यमियों को अपने विचारों को स्थायी व्यावसायिक मॉडल में बदलने के लिए सशक्त बनाना है।

(ii) प्रतिभागियों की मेजबानी करने वाले संस्थानों को राष्ट्रीय ब्रांडिंग के अवसर, क्षेत्रीय स्तर की चुनौतियों का आयोजन करने के अवसर, तथा प्रतियोगिता में अपने छात्रों के प्रदर्शन और उपलब्धियों के माध्यम से बेहतर राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग के साथ महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा।

(iii) यह पहल सीधे तौर पर विकसित भारत मिशन से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर, समावेशी और नवाचार-संचालित भारत का निर्माण करना है। छात्रों में उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देकर, यह कार्यक्रम सतत विकास, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान देता है।

8. DAHD ने पूरे भारत में ग्लैंडर्स से निपटने के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया।



मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (MoFAHD) के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) ने ग्लैंडर्स पर एक संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है, जिसका उद्देश्य इस घातक अश्व रोग की निगरानी, प्रतिक्रिया और उन्मूलन को बढ़ाना है। अगस्त 2025 में प्रकाशित होने वाली यह योजना पशु कल्याण और जन स्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा के लिए एक मज़बूत वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाती है।

● अद्यतन रणनीति रोग निगरानी और रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल का विस्तार करती है, जिससे स्थानिक क्षेत्रों में अनिवार्य परीक्षण अनिवार्य हो जाता है। यह योजना प्रयोगशाला निदान को उन्नत करने, वास्तविक समय में क्षेत्रीय निरीक्षण लागू करने और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रणालियों में एक डिजिटल रिपोर्टिंग नेटवर्क स्थापित करने का समर्थन करती है।

● एक सुव्यवस्थित त्वरित प्रतिक्रिया और रोकथाम ढांचा, प्रभावित घोड़ों को शीघ्र पृथक करने, पॉजिटिव मामलों को मानवीय तरीके से निपटाने, तथा प्रसार को रोकने के लिए सटीक रोकथाम कार्यों के लिए DAHD और राज्य पशुपालन विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है।

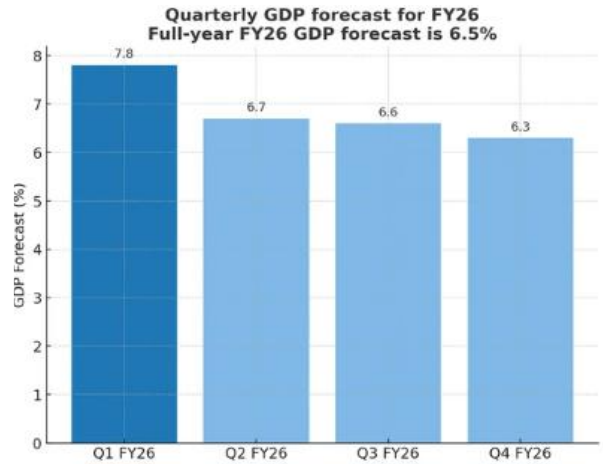
Key Points:-

(i) क्षमता निर्माण पहल इस योजना का अभिन्न अंग हैं, जिसमें पशु चिकित्सकों और अर्ध-पशु चिकित्सा कर्मियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण शामिल है। इस कार्यक्रम में रोग पहचान, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल और अग्रिम पंक्ति के पशु चिकित्सा कर्मियों के लिए सटीक रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं पर व्यावहारिक कार्यशालाएँ शामिल हैं।

(ii) सामुदायिक पहुँच और हितधारक सहभागिता प्रमुख घटक हैं, जिनमें घोड़ों के मालिकों, प्रजनकों और व्यापारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए जागरूकता अभियान शामिल हैं। ये प्रयास शीघ्र सूचना देने, निवारक उपायों को अपनाने और जमीनी स्तर पर विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

(iii) शोध और संस्थागत दृष्टिकोण से, ICAR -राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र (NRCE), हिसार, नैदानिक क्षमताओं को बढ़ाकर, महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन करके और प्रयोगशाला दक्षता कार्यक्रमों का नेतृत्व करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी प्रयास वन हेल्थ फ्रेमवर्क के अनुरूप हैं, संभावित जूनोटिक जोखिमों को पहचानते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य रणनीतियों पर ज़ोर देते हैं।

9. भारत ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8% GDP वृद्धि दर्ज की, जो सेवाओं और विनिर्माण द्वारा संचालित पांच तिमाहियों में सबसे अधिक है।



2025 की अप्रैल-जून तिमाही (वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही) में, भारत की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय 7.8% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 6.5% से कहीं अधिक थी और पाँच तिमाहियों में सर्वोच्च स्तर पर थी। यह मज़बूत प्रदर्शन पूर्व-तिमाही पूर्वानुमानों से कहीं अधिक था, जो अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाता है।

● भारत का सेवा क्षेत्र 9.3% की वृद्धि के साथ अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में उभरा, जिसमें वित्तीय, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएँ, और व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार उप-क्षेत्रों में तेज़ी से वृद्धि हुई। विनिर्माण क्षेत्र ने भी 7.7% की मज़बूत वृद्धि दर्ज की, जिसमें 85% वृद्धिशील सकल मूल्य वर्धन (GVA) इन दोनों क्षेत्रों से आया।

● इस बीच, कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने स्थिर 3.7% का योगदान दिया, और समग्र उद्योग क्षेत्र में 6.3% की वृद्धि हुई, जो व्यापक आर्थिक लाभ को रेखांकित करता है।

● व्यय के मोर्चे पर, उपभोक्ता मांग मजबूत बनी रही: निजी खपत में 7% की वृद्धि हुई, सरकारी खर्च में 7.4% की वृद्धि हुई, और सकल पूंजी निर्माण (कैपेक्स) में 7.8% की वृद्धि हुई, जो परिवारों, सार्वजनिक निवेश और व्यावसायिक निवेशों में मजबूत आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) यह वृद्धि बढ़ते व्यापार तनाव जैसी बाहरी चुनौतियों के बावजूद दर्ज की गई। गौरतलब है कि अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत का GDP विस्तार उम्मीदों से कम रहा, जो घरेलू मांग और आर्थिक बुनियादी ढांचे की मजबूती को दर्शाता है।

(ii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के सरकारी आंकड़ों ने पुष्टि की कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही की GDP वृद्धि 7.8% थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 6.5% के पूर्वानुमान और अन्य संस्थागत अनुमानों 6.7% से काफी अधिक थी।

(iii) आर्थिक विश्लेषकों और उद्योग मंडलों ने इस खबर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। एसोचैम और फिक्की ने पहली तिमाही के प्रदर्शन को भारत के लचीलेपन और वित्त वर्ष 26 की मजबूत शुरुआत का प्रमाण बताया, जिससे कारोबारी धारणा में सुधार की संभावना है। इस बीच, नीति निर्माताओं ने इन आंकड़ों का इस्तेमाल भारत को एक मजबूत और बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए किया—जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद गति बनाए हुए है।



भारत ने भारतीय सशस्त्र बलों और मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (IDS) से 700 से अधिक कर्मियों को अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए तैनात किया है, जो कि एक प्रमुख बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास है, जो 28 अगस्त से 10 सितंबर, 2025 तक मिस्र के मतरूह गवर्नरिट में मोहम्मद नगुइब सैन्य अड्डे पर आयोजित किया जा रहा है।

● अभ्यास ब्राइट स्टार का वर्तमान संस्करण इस श्रृंखला का 19वाँ संस्करण है और इसे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले बहुराष्ट्रीय रक्षा अभ्यासों में से एक माना जाता है। भारत की भागीदारी क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और वैश्विक साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

● ब्राइट स्टार अभ्यास को 1978 के कैप डेविड समझौते के बाद, 1980 में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और मिस्र के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में, यह फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम (UK), जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों की भागीदारी के साथ एक बहुपक्षीय प्रारूप में विस्तारित हुआ।

● इस वर्ष के अभ्यास में 43 देश भाग लेंगे, जिनमें से 13 देश लगभग 7,900 सैनिक तैनात करेंगे, जबकि लगभग 30 देश अपने सैन्य पर्यवेक्षक भेजेंगे। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायु सेना की

INTERNATIONAL

1. भारत ने 700 से अधिक कर्मियों के साथ मिस्र में बहुपक्षीय 'अभ्यास ब्राइट स्टार 2025' में भाग लिया।

तीनों सेनाओं के घटक शामिल होंगे, और प्रशिक्षण संयुक्त योजना, लाइव-फायर प्रदर्शन, विषय-वस्तु के आदान-प्रदान और परिचालन समन्वय पर केंद्रित होगा।

Key Points:-

- (i) ब्राइट स्टार 2025 के लिए भारत के दल में भारतीय सेना (IA), भारतीय नौसेना (IN) और भारतीय वायु सेना (IAF) के कर्मी शामिल हैं, जिन्हें मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा समर्थन दिया जाता है।
- (ii) भारतीय पक्ष साझेदार देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करेगा, जिसमें परिचालन योजना, लघु अवधि मिशन, आतंकवाद विरोधी रणनीतियां और मानवीय सहायता अभियान शामिल होंगे।
- (iii) 2023 में आयोजित पिछले संस्करण में, भारत ने लगभग 550 तीनों सेनाओं के कर्मियों को तैनात करके पहली बार भाग लिया था। 2025 में उन्नत सैन्य टुकड़ी के साथ, भारत की भूमिका साझेदार देशों के साथ उसकी बढ़ती रणनीतिक भागीदारी और बहुपक्षीय रक्षा ढाँचे के भीतर मज़बूत सैन्य-से-सैन्य संबंध बनाने की उसकी आकांक्षा को दर्शाती है।

BANKING & FINANCE

1. जियो पेमेंट्स बैंक ने निष्क्रिय जमा पर उच्च रिटर्न के लिए 'सेविंग्स प्रो' लॉन्च किया।



अगस्त 2025 में, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (JFSL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (JPBL) ने 'सेविंग्स प्रो' पेश किया, जो भारत का पहला बचत खाता है जो स्वचालित रूप से रातोंरात म्यूचुअल फंड (MFs) में निष्क्रिय शेष राशि का निवेश करता है, जिससे जमाकर्ताओं को अतिरिक्त प्रयास के बिना उच्च रिटर्न अर्जित करने में मदद मिलती है।

• इस लॉन्च की आधिकारिक घोषणा जेएफएसएल के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हितेश सेठिया ने कंपनी की 2024-25 की वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान की। यह पारंपरिक जमाओं को ओवरनाइट म्यूचुअल फंड (MF) से जोड़कर भारत के बैंकिंग नवाचार में एक मील का पत्थर है।

• 'सेविंग्स प्रो' को बचत खाते की ब्याज दरों में लगभग 2.5% की गिरावट को दूर करने के लिए पेश किया गया था, जिससे ग्राहकों को निष्क्रिय शेष राशि को ओवरनाइट MF में स्थानांतरित करने में मदद मिली, जो आम तौर पर प्रति वर्ष 4% से 6% के बीच रिटर्न देते हैं, जो पारंपरिक बचत खातों की तुलना में काफी अधिक है।

Key Points:-

- (i) इस उत्पाद को भुगतान बैंक विनियमों के अनुसार प्रति ग्राहक 2 लाख रुपये की जमा सीमा के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे यह दीर्घकालिक निवेश के बजाय अल्पकालिक अधिशेष नकदी प्रबंधन और आपातकालीन निधि पार्किंग चाहने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त है।
- (ii) इस व्यवस्था के तहत, ग्राहक के खातों में निष्क्रिय शेष राशि स्वचालित रूप से और निर्बाध रूप से ओवरनाइट डेट म्यूचुअल फंडों में निवेश कर दी जाती है, जो अगले दिन परिपक्व होने वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये फंड ओपन-एंडेड, कम जोखिम वाले होते हैं और इनमें न्यूनतम हस्तक्षेप

की आवश्यकता होती है, जिससे तरलता के साथ सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

(iii) इस नवाचार की पेशकश करके, जियो पेमेंट्स बैंक का लक्ष्य बचत खाते की तरलता को म्यूचुअल फंड के बढ़े हुए रिटर्न के साथ जोड़ना है, जिससे ग्राहकों को सक्रिय वित्तीय प्रबंधन के बिना निष्क्रिय धन का अनुकूलन करने का एक सरल, स्वचालित तरीका मिल सके।

2. यूनिटी बैंक और भारतपे ने भारत का पहला EMI-संचालित रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।



अगस्त 2025 में, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (यूनिटी बैंक) ने भारतपे के साथ मिलकर भारत का पहला समान मासिक किस्त (ईएमआई) आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसे 'यूनिटी बैंक भारतपे क्रेडिट कार्ड' कहा गया है। यह कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित रुपये नेटवर्क पर काम करता है और यूपीआई-सक्षम है, जो पारदर्शी और समावेशी ऋण सुविधा प्रदान करता है।

• यूनिटी बैंक भारतपे क्रेडिट कार्ड में एक ऑटो-ईएमआई रूपांतरण सुविधा शामिल है, जिसके तहत 1000 रुपये से अधिक के किसी भी मासिक अवैतनिक खर्च को स्वचालित रूप से ईएमआई में बदल दिया जाता है, और 12 महीने तक के लचीले पुनर्भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं। यह व्यवस्था

वेतनभोगी और स्व-नियोजित व्यक्तियों को अपने नकदी प्रवाह का ज़िम्मेदारी से प्रबंधन करने और उच्च-ब्याज वाले ऋण जाल से बचने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

• यह कार्ड शून्य-शुल्क संरचना प्रदान करता है, जिससे सदस्यता शुल्क, वार्षिक शुल्क या ज़ब्ती दंड समाप्त हो जाते हैं। यह इसे भारत में सबसे किफायती क्रेडिट विकल्पों में से एक बनाता है, खासकर मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए जो अक्सर छिपे हुए शुल्क और दंड प्रावधानों के कारण पारंपरिक क्रेडिट कार्ड से बचते हैं।

• यूनिटी बैंक भारतपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार, आवेदकों की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए न्यूनतम वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपये होनी चाहिए। यह समावेशी ढाँचा सुनिश्चित करता है कि शहरी पेशेवर और छोटे व्यवसाय के मालिक, दोनों ही संरचित और सुलभ ऋण का लाभ उठा सकें।

Key Points:-

(i) इसके लाभों के भाग के रूप में, यह कार्ड EMI-परिवर्तित लेनदेन पर 2% का असीमित रिवॉर्ड प्रदान करता है, जिसे वाउचर, बिल भुगतान या 5,000 रुपये तक के मूल्य के उत्पादों के लिए ज़िलियन कॉइन के रूप में भुनाया जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्त, कार्ड में जीवनशैली संबंधी विशेषाधिकार जैसे कि मानार्थ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लाउंज का उपयोग, स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के लिए निर्बाध यूपीआई एकीकरण शामिल हैं।

(iii) कुल मिलाकर, यूनिटी बैंक भारतपे क्रेडिट कार्ड, सामर्थ्य, रिवॉर्ड और डिजिटल-फर्स्ट सुविधाओं को मिलाकर, जिम्मेदार क्रेडिट उपयोग और वित्तीय सशक्तिकरण सुनिश्चित करके भारत के क्रेडिट परिदृश्य में एक अग्रणी कदम का प्रतिनिधित्व करता

है।

3. SBI कार्ड और फ्लिपकार्ड ने सहज खरीदारी के लिए सह-ब्रांडेड 'फ्लिपकार्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड' लॉन्च किया।



अगस्त 2025 में, एक प्रमुख भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस में से एक, फ्लिपकार्ड के साथ मिलकर नई दिल्ली में 'फ्लिपकार्ड SBI क्रेडिट कार्ड' लॉन्च किया। इस लॉन्च का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं को विशेष कैशबैक लाभों के साथ एक सहज खरीदारी अनुभव प्रदान करना है।

● फ्लिपकार्ड SBI क्रेडिट कार्ड को आधिकारिक तौर पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु (सी.एस.) सेट्टी और SBI के प्रबंध निदेशक (MD) अश्विनी कुमार की उपस्थिति में लॉन्च किया गया, जो भारत में डिजिटल भुगतान समाधान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

● लॉन्च कार्यक्रम में वित्तीय समावेशन और ग्राहक सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बैंकों और ई-कॉमर्स कंपनियों के बीच साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

● यह नया लॉन्च किया गया को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मास्टरकार्ड और वीज़ा दोनों प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है, जिससे यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापक रूप से उपलब्ध है। ग्राहक फ्लिपकार्ड मोबाइल एप्लिकेशन, एसबीआई कार्ड स्प्रिंट, या आधिकारिक कार्ड वेबसाइट 'SBICard.com' के माध्यम से आसानी से डिजिटल रूप से आवेदन कर सकते हैं, जिससे तेज़ और उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित होती है।

Key Points:-

(i) फ्लिपकार्ड SBI क्रेडिट कार्ड चुनिंदा कैशबैक ऑफ़र के साथ आता है, जिसमें मित्रा पर खरीदारी पर 7.5% कैशबैक और फ्लिपकार्ड, शॉप्सी और क्लियरट्रिप पर खर्च पर 5% कैशबैक शामिल है। ये लाभ प्रत्येक श्रेणी के लिए 4,000 रुपये की त्रैमासिक कैशबैक सीमा के अधीन हैं, जिससे नियमित ऑनलाइन खरीदारी करने वालों को अपनी बचत को अधिकतम करने का अवसर मिलता है।

(ii) इस को-ब्रांडेड कार्ड की एक अनूठी विशेषता स्वचालित कैशबैक क्रेडिट प्रणाली है। इस सुविधा के तहत, हकदार कैशबैक स्टेटमेंट जनरेट होने के दो दिनों के भीतर ग्राहक के एसबीआई खाते में स्वतः जमा हो जाता है, जिससे मैनुअल रिडेम्पशन की आवश्यकता कम हो जाती है और उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित होता है।

(iii) इस लॉन्च के ज़रिए, SBI कार्ड और फ्लिपकार्ड का लक्ष्य भारत के बढ़ते डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र, खासकर खुदरा और यात्रा क्षेत्रों में, को अपने साथ जोड़ना है। इस सहयोग से उपभोक्ताओं को ज़्यादा वित्तीय लचीलापन और रिवॉर्ड-आधारित खरीदारी का लाभ मिलने की उम्मीद है, साथ ही भारत में अग्रणी क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं में से एक के रूप में SBI की स्थिति और मजबूत होगी।

MOUs and Agreement

1. SIA-भारत और EIAPI ने इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



28 अगस्त, 2025 को, सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन-इंडिया (SIA-इंडिया) ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ द फिलीपींस इंक. (EIAPI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना है, साथ ही भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाना है।

- यह समझौता ज्ञापन मुख्य रूप से उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और उत्पाद विकास पर केंद्रित है। इनमें उपग्रह संचार हार्डवेयर, एम्बेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरण और अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जो भारत-फिलीपींस प्रौद्योगिकी सहयोग को और मज़बूत करेंगे।

- इस समझौते के माध्यम से, दोनों पक्ष एक सहयोगात्मक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए काम करेंगे। यह पारिस्थितिकी तंत्र फिलीपींस को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण आधार, जिसका वर्तमान मूल्य 115 बिलियन

अमेरिकी डॉलर है, से लाभान्वित करेगा और वैश्विक प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करेगा।

Key Points:-

(i) यह समझौता ज्ञापन सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यह द्विपक्षीय सहयोग में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।

(ii) भविष्य में, इस साझेदारी से दोनों देशों में स्टार्टअप, शैक्षणिक-उद्योग साझेदारी और कार्यबल कौशल विकास के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

(iii) भारत की तकनीकी ताकत को फिलीपींस के बढ़ते नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जोड़कर, यह समझौता दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सतत विकास में योगदान देता है।

SPORTS

1. धर्मबीर नैन, प्रीति पाल को विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया।



अगस्त 2025 में, भारतीय पैरालंपिक समिति (PCI) ने आधिकारिक तौर पर पैरालंपियन धर्मबीर नैन और प्रीति पाल को 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप

2025 के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक घोषित किया। यह चैंपियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। यह पहली बार होगा जब भारत इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा।

- यह घोषणा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व अब तक का सबसे बड़ा 73 सदस्यीय दल करेगा, जो टूर्नामेंट में 107 से अधिक देशों के प्रतिभागियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा।

- पेरिस 2024 पैरालिंपिक में पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरालिंपियन धर्मबीर नैन और पेरिस 2024 पैरालिंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर T35 दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतने वाली प्रीति पाल को भारत का ध्वजवाहक चुना गया। उनका चयन पैरा-एथलेटिक्स में भारत के बढ़ते प्रभुत्व का प्रतीक है।

- 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। यह आयोजन भारतीय पैरालिंपिक समिति (PCI) के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि भारत पहली बार इस चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है।

Key Points:-

(i) भारत 73 एथलीटों का एक मजबूत दल उतारेगा, जो किसी भी पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उसका सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व होगा। विश्व स्तर पर, 107 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है, जिससे यह विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन जाएगा।

(ii) पेरिस 2024 में धर्मबीर नैन के स्वर्ण पदक ने फील्ड स्पर्धाओं में भारत की ताकत को उजागर किया, जबकि प्रीति पाल ने एक ही पैरालिंपिक में दो ट्रैक और फील्ड पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। उनकी उपलब्धियों

ने न केवल भारत की पदक तालिका को बढ़ाया, बल्कि देश भर के नए एथलीटों को भी प्रेरित किया।

(iii) बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को इस चैंपियनशिप का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य भारत में पैरा-स्पोर्ट्स के प्रति लोगों की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाना है। इस आयोजन की मेज़बानी वैश्विक खेल पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की भूमिका को और मज़बूत करती है और एथलेटिक्स में समावेशिता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

2. नीरज चोपड़ा 2025 डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे।



2025 डायमंड लीग सीज़न के रोमांचक समापन में, भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में 85.01 मीटर के क्लच फाइनल थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता।

- नीरज चोपड़ा ने पूरे सत्र में अपने प्रदर्शन की बंदौलत, जिसमें दोहा और पेरिस जूनियर लीग मीट में उल्लेखनीय भागीदारी भी शामिल है, 27-28 अगस्त, 2025 को ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग फाइनल के लिए पहले ही अर्हता प्राप्त कर ली थी।

● नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनके छठे और अंतिम प्रयास में आया, जहाँ उन्होंने भाला 85.01 मीटर तक फेंका और दूसरे स्थान पर पहुँच गए। इससे पहले, उन्होंने 84.35 मीटर और 82.00 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था, जिसके बाद तीन फ़ाउल हुए थे।

Key Points:-

(i) जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर की विजयी थ्रो के साथ चोपड़ा को छह मीटर से अधिक पीछे छोड़ दिया और स्पष्ट श्रेष्ठता के साथ डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया।

(ii) नीरज चोपड़ा ने खुद स्वीकार किया कि उनकी टाइमिंग और रन-अप में गड़बड़ी हुई और तकनीकी खामियों ने उनके प्रदर्शन को प्रभावित किया। इसके बावजूद, वह आशावादी बने हुए हैं और इस परिणाम को टोक्यो में होने वाली आगामी विश्व चैंपियनशिप से पहले सीखने का एक अवसर मान रहे हैं।

(iii) यह चोपड़ा का चार डायमंड लीग फ़ाइनल में तीसरा दूसरा स्थान है: उन्होंने इससे पहले 2022 में जीत हासिल की थी और 2023 और 2024 दोनों में दूसरे स्थान पर रहे थे। उनकी निरंतरता वैश्विक एथलेटिक्स में उनकी विशिष्ट स्थिति को रेखांकित करती है।

IMPORTANT DAYS

1. राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2025, 30 अगस्त को मनाया गया।



भारत ने देश भर में आर्थिक विकास को गति देने, रोज़गार सृजन करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में लघु उद्योगों (SSI) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में 30 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस (NSID) 2025 मनाया।

● राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की शुरुआत 30 अगस्त 2000 को हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नई दिल्ली में लघु उद्योगों पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान SSI के लिए एक व्यापक नीति पैकेज का शुभारंभ किया था।

● इस नीतिगत पहल को चिह्नित करने के लिए, भारत सरकार (GoI) ने आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में घोषित किया, जिसकी शुरुआत 2001 में हुई और 2025 को यह दिवस 25वीं बार मनाया गया।

Key Points:-

(i) यह वार्षिक उत्सव भारत की अर्थव्यवस्था में MSMEs की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देता है, कुल निर्यात में लगभग 48% का योगदान देता है और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) उद्यमिता को बढ़ावा देने, नवाचार को

मजबूत करने और लघु व्यवसायों के विकास हेतु कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए NSID पर विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सम्मान समारोहों का आयोजन करता है।

(iii) विश्व स्तर पर, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र (UN) MSME दिवस के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में लघु उद्योगों की भूमिका को रेखांकित करता है।

DEFENCE

1. भारत-बांग्लादेश ने 25-28 अगस्त 2025 तक ढाका में 56वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन आयोजित किया।



25 से 28 अगस्त 2025 तक, भारत और बांग्लादेश ने ढाका में 56वां महानिदेशक-स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्देश्य सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना था। इस सम्मेलन में दोनों देशों के सीमा प्रमुखों के साथ-साथ गृह, विदेश और सीमा एजेंसियों के अधिकारी द्विपक्षीय चिंताओं पर विचार-विमर्श के लिए एकत्रित हुए।

● चार दिवसीय यह सम्मेलन ढाका के पिलखाना स्थित बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) मुख्यालय में आयोजित हुआ और इसमें बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफज्जमां सिद्दीकी और

बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। भारतीय पक्ष में गृह मंत्रालय (MHA), विदेश मंत्रालय (MEA) और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 11 सदस्य शामिल थे, जबकि BGB ने कई राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था।

● 1970 के दशक के मध्य में शुरू की गई ये महानिदेशक-स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें, निरंतर संवाद और मजबूत सीमा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1993 में द्विवार्षिक कर दी गई। यह आयोजन फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 55वें सम्मेलन के बाद हो रहा है।

● मुख्य विषयों में सीमा पर होने वाली हत्याओं में कमी, अवैध घुसपैठ और अनधिकृत पारगमन पर अंकुश, नशीली दवाओं, हथियारों और प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को रोकना और विद्रोही गतिविधियों से निपटना शामिल था। सीमा के 150 गज के दायरे में अनधिकृत निर्माण को रोकने, नदी तटों के संरक्षण और जल के उचित बंटवारे को सुनिश्चित करने की योजनाओं पर भी प्रमुखता से चर्चा हुई।

Key Points:-

(i) दोनों पक्षों ने एकीकृत सीमा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त की, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा की, संयुक्त गश्त की और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर सहमति व्यक्त की। अगला सम्मेलन मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

(ii) बांग्लादेश ने BSF कर्मियों द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों पर गोलीबारी और उन्हें घायल करने सहित बार-बार होने वाली हिंसा की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिससे सार्वजनिक तनाव बढ़ गया है। भारत ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमों के

सख्त पालन, रात्रि गश्त बढ़ाने और सहयोगात्मक प्रयासों का आश्वासन दिया।

(iii) चर्चा सुरक्षा से आगे बढ़कर भारतीय मीडिया में बांग्लादेश विरोधी दुष्प्रचार जैसे विवादास्पद मुद्दों पर भी केंद्रित रही। सीमा संबंधी चिंताओं के साथ-साथ इन संवेदनशीलताओं पर ध्यान देने से दोनों देशों में राजनीतिक बदलावों के बीच द्विपक्षीय संतुलन बनाए रखने की व्यापक प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई।

Static GK

MoSPI	मंत्री: राव इंद्रजीत सिंह	मुख्यालय: नई दिल्ली
MoE	केंद्रीय मंत्री: धर्मेन्द्र प्रधान	मुख्यालय: नई दिल्ली
Bihar	मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार	राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
Egypt	राजधानी: काहिरा	राष्ट्रपति: अब्देल फतह अल- सीसी
Bangladesh	अध्यक्ष: मोहम्मद शहाबुद्दीन	राजधानी: ढाका
HCL Technologies Limited (HCLTech)	CEO : सी विजयकुमार	मुख्यालय: नोएडा
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying (MoFAH&D)	केंद्रीय मंत्री: राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	मुख्यालय: नई दिल्ली